जनसत्ता

हालात और चुनौती

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के जो संकेत आ रहे हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि आर्थिकी के क्षेत्र में सब कुछ संतोषजनक नहीं है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत बताता है कि उद्योग, कारोबार, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों की हालत न तो पिछले कुछ समय में अच्छी रही है और न आने वाले महीनों में अच्छी रहनी है। बैंकिंग क्षेत्र एनपीए की मार झेल रहा है। वित्तीय क्षेत्र की हालत भी कोई मजबूत नहीं है। रोजगार भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। वर्तमान में रोजगार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साढ़े चार दशक में इस वक्त बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर पर है। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उससे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू कारणों के अलावा बाहरी कारण भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यह कह रहा है कि पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में अर्थव्यवस्था सुस्त रही तो इससे भविष्य का भी संकेत मिलता है।

आखिर क्या कारण हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। सरकार की ओर से तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो यह कि मांग में कमी बनी रही, जिससे घरेलू उपभोक्ता बाजार कमजोर बना रहा। दूसरी वजह स्थायी निवेश में बढ़ोतरी न के बराबर हुई। तीसरा कारण निर्यात सुस्त रहना था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने इस साल फरवरी में 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 फीसद से घटा कर सात फीसद कर दिया था। पिछले पांच साल में यह पहला मौका है जब आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सबसे कम है। हालांकि पिछले महीने रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती का जो कदम उठाया था, उसका मकसद ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में बढ़ना था। रिजर्व बैंक के अलावा अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी की बात कही थी। एडीबी ने वैश्विक हालात के मद्देनजर भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को 7.6 फीसद से घटा कर 7.2 फीसद कर दिया था। फिच ने अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कम रफ्तार की बात कही थी और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6.8 फीसद जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया था, जो पहले सात फीसद था। जाहिर है, हालात कई महीनों से ऐसे बने हुए हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था की दर पर असर पड़े बिना रह नहीं सकता।

सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उदार और तर्कसंगत कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि भारत के लिए आने वाले दिन ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, खासकर ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी और निर्यात के मोर्चे पर स्थिति मजबूत करने के लिए। हालात चिंताजनक इसलिए हैं कि देश का विनिर्माण क्षेत्र डगमगाया हुआ है। आम चुनाव की वजह से भी अनिश्चितता का माहौल है, जिसका आर्थिकी पर असर पड़ रहा है। इस अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले आठ महीने में सबसे कम रही। इस क्षेत्र में सुस्ती का मतलब है कि बाजार में खरीदार नहीं हैं। खर्च घटाने के लिए कंपनियां नौकरियों में कटौती कर रही हैं। आज जो हालात बने हुए हैं उनमें जल्द सुधार के आसार नजर नहीं आ रहे। नई सरकार अर्थव्यवस्था के लिए क्या, कैसी नीतियां बनाती है, काफी कुछ इस पर ही निर्भर करेगा।

उत्साहजनक नतीजे

परीक्षाओं के नतीजे विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई में रुचि के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी रेखांकित करते हैं। इस लिहाज से इस साल भी सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारहवीं के नतीजे उत्साहजनक कहे जा सकते हैं। इसमें फिर एक बार लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। सर्वाधिक अंक हासिल करने वालों में लड़कियों की संख्या अधिक है। फिर अधिकतम पांच सौ में से चार सौ निन्यानबे अंक यानी महज एक अंक कम हासिल कर दो लड़कियों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना भी गौरव की बात है। इसमें एक उपलब्धि यह भी शुमार है कि केंद्रीय विद्यालयों ने परीक्षाफल के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उनमें पढ़ने वाले साढ़े अठानबे फीसद से ऊपर विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दूसरे स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालयों का प्रदर्शन रहा, जो कि पिछड़े इलाकों के होनहार विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से चलाए जाते हैं। निजी स्कूलों का प्रदर्शन तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा शहरों के हिसाब से त्रिवेंद्रम पहले, चेन्नई दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहे। इन आंकड़ों से यह साफ है कि शिक्षा के प्रति रुझान महानगरों की अपेक्षा कम सुविधा संपन्न इलाकों के विद्यार्थियों में अधिक है। दिल्ली जैसे शहर, जहां पढ़ाई-लिखाई के मामले में अधिक सतर्कता और निजी स्कूलों में व्यावसायिक होड़ दिखाई देती है, वहां के स्कूलों का प्रदर्शन अगर नीचे खिसक रहा है, तो इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता।

हालांकि पिछले कुछ सालों से सीबीएसई के नतीजों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सीबीएसई की तुलना में राज्यों के शिक्षा बोर्डों के नतीजे काफी नीचे दर्ज होते हैं। इसकी कुछ वजहें तो साफ हैं। एक तो यह कि राज्य शिक्षा बोर्डों के तहत चलने वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हो पाए हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब दोनों बोर्डों के बच्चे साथ बैठते हैं तो राज्य बोर्डों के बच्चे कमजोर साबित होते हैं। इस तरह राज्य बोर्डों से पढ़े अनेक होनहार बच्चे भी बेहतर माने जाने वाले शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने से रह जाते हैं। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में सीबीएसई के नतीजों के आधार पर कट-ऑफ सूची जारी की जाती है, जिसमें निजी स्कूलों या सीबीएसई पाठ्यक्रमों वाले बच्चे आसानी से जगह बना पाते हैं, जबकि राज्य बोर्डों के बच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। इस तरह परीक्षा परिणामों के आधार पर समाज में शिक्षा की दो स्पष्ट धाराएं बन गई हैं।

फिर यह सवाल कई सालों से उठ रहा है कि क्या वजह है कि विद्यार्थी साहित्य तक के पर्चे में पूरे के पूरे अंक हासिल कर ले रहे हैं। एक-दो नंबर कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक होती है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में, जहां सवाल हल करने के तरीके और उनके उत्तर निर्धारित हैं, उनमें पूरे के पूरे अंक पाना हैरानी की बात नहीं। मगर साहित्य और समाज विज्ञान के विषयों में जहां बोध और अभिव्यक्ति के प्रश्न होते हैं, उनमें महज एकाध नंबर कटना स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन पद्धति पर सवाल खड़े करता है। हालांकि सीबीएसई का दावा है कि उसकी मूल्यांकन पद्धति बहुत वैज्ञानिक है और उसकी पुस्तिकाएं जांचने वाले देश भर के योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। मगर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि साहित्य और समाज विज्ञान के बोध प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वे अकाट्य तर्क रखते होंगे।

कल्पमेधा

मानव जीवन में लगन बड़े महत्त्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, जिसमें लगन नहीं है वह जवान भी मृतक है।

-प्रेमचंद

खुदकुशी से उपजते सवाल

ज्योति सिडाना

आज शैक्षणिक असफलता का भय इतना व्यापक हो गया है कि उसके सामने जीवन तुच्छ नजर आने लगा है। सवाल है कि क्या हत्या और आत्महत्या समस्याओं का एकमात्र समाधान रह गए हैं? अगर इसका जवाब 'हां' है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य, परिवार या फिर बाजार? आज समाज पर उपभोक्तावाद इतना हावी है कि समृद्धि की चाहत में भावनाएं, रिश्ते, प्रेम सब कुछ हाशिये पर कर दिए गए हैं।

ऐसा माना जाता है कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी (18 से 35 वर्ष आयु वाला समूह) वाला देश है, जो देश की कुल आबादी का लगभग इकतीस फीसद है। जिस देश में युवा शक्ति सर्वाधिक हो उस देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की युवा आबादी 26.9 करोड़ और अमेरिका की साढ़े छह करोड़ है, जो भारत के मुकाबले कम है। फिर भी ये देश विश्व की महाशक्तियों में शामिल किए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अपनी बड़ी युवा आबादी के साथ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं नई ऊंचाइयां छू सकती हैं, बशर्ते वे युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य में भारी निवेश करें और उनके अधिकारों का संरक्षण करें। अगर हमारे देश में ऐसी आबादी का इकतीस फीसद हिस्सा उपस्थित है तो इस देश में विकास की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं! लेकिन पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों और युवाओं की बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति विकास की इस संभावना को धूमिल करती नजर आती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति राज सत्ता, प्रशासन और समाज के लिए शायद चिंता व चर्चा का विषय नहीं रह गई है।

कुछ दिन पूर्व ही तेलंगाना में बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद एक हफ्ते में बीस विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। इस साल वहां 9.74 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से तीन लाख विद्यार्थी असफल रहे। अभिभावकों के अनुसार आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के परीक्षा परिणामों में उच्चतम अंक हासिल कर चुके थे, इसलिए उन्हें अपनी असफलता पर विश्वास नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब एक विद्यार्थी को बारहवीं कक्षा में तेलुगु में शून्य अंक मिला और पुनर्मूल्यांकन कराने पर उसके अंक बढ़ कर निन्यानवे हो गए। मीडिया की मानें तो इस वर्ष परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य किसी निजी फर्म को दिया गया था जो पहले से ही कई अनियमिताओं के आरोपों में घिरी है। इस पर फर्म का कहना है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो गया। यानी सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण मेधावी बच्चों को पांच से दस अंक मिले, सौ से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित होने के बावजूद अनुपस्थित दिखा दिए गए। फर्म की इस लापरवाही के कारण बीस प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवा दी।

यहां सवाल उठता है कि इसे आत्महत्या माना जाए या सुनियोजित हत्या? यह घटना केवल तेलंगाना की शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था की खामियों को ही उजागर नहीं करती, अपितु संपूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी ही तस्वीर उभर कर आई है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में भी दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद बारह बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी। ये तो वे आंकड़े हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चो के हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तो और ज्यादा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आइआइटी, मेडिकल, सिविल सर्विस आदि में असफल होने के बाद खुदकुशी जैसा कदम उठाते हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में अकेले कोटा (राजस्थान) में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उन्नीस विद्यार्थियों ने खुदकुशी कर ली थी।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आजकल इंटरनेट पर सर्वाधिक खोजा जाने वाला विषय है-'दर्द रहित मौत' (पेनलैस सुसाइड)। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, उसमें संवादहीनता की स्थिति बहुत हद तक बढ़ गई है। साथ ही, बच्चों व अभिभावकों के मध्य असंतुलित संबंध, अत्यधिक अपेक्षाएं, मित्रों या प्रेम संबंधों में खटास आना, पढ़ाई का तनाव, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ मानना इत्यादि मुख्य कारण हैं जो विद्यार्थियों को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाते हैं। एक समय था जब परीक्षा या प्रतियोगिता में असफल होने पर परिवारजन अथवा अभिभावक कहते सुने जाते थे कि कोई बात नहीं अगली बार ज्यादा मेहनत कर लेना और अब माता-पिता ही बच्चों की असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज सफलता का मतलब है जिंदगी और असफलता का मतलब है आत्महत्या। आज हम किस तरह की युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसने जीवन में संघर्ष शुरू होने से पहले ही हार मान ली, जिसके लिए जीत और सिर्फ जीत एक मात्र लक्ष्य रह गया है।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर घंटे एक विद्यार्थी

आत्महत्या कर लेता है और एक दिन में पच्चीस। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने का प्रमुख कारण शैक्षणिक तनाव है। मोटा वेतन हासिल करने वाले सफल विद्यार्थियों की कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में प्रमुखता से स्थान प्राप्त करती हैं और दूसरे बच्चों के माता-पिता को प्रेरित करती हैं कि वे भी अपने बच्चों से इस तरह की अपेक्षाएं रखें। आज के प्रतियोगिता मूलक समाज में यह बहुत सामान्य-सी बात हो गई है कि बहुत ही छोटी उम्र में अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलवा देते हैं ताकि वे किसी प्रतिष्ठित आइआइटी या मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा सकें। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत से गुजरना होता है, बारह से चौदह घंटे पढ़ाई में व्यस्त रहना, लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, पारिवारिक उत्सवों और त्योहारों में सहभागिता से वंचित रहना, महीनों छुट्टियां नहीं मिलना, हफ्ते या दो हफ्ते के नियमित अंतराल पर मूल्यांकन परीक्षा देना, मनोरंजन एवं खेल के संसाधनों से दूर रहना.. आदि ऐसे कारण हैं जो विद्यार्थी से उनका स्वाभाविक जीवन छीन लेते हैं और वे एक मशीन बन कर रह जाते हैं।

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि जाति-आधारित भेदभाव भारत में विद्यार्थियों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। वर्ष 2007 में थोराट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जाति के आधार पर विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव देखा जाता है जिसके चलते वे आत्महत्या कर लेते हैं। थोराट कमेटी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित जांच के लिए बैठाई गई थी। इसी तरह कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि बेरोजगारी भी भारत में छात्रों की आत्महत्या का एक मुख्य कारण है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद है जो पिछले साढ़े चार दशक वर्षों में सर्वाधिक है। शिक्षा का निजीकरण भी काफी हद तक इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

सन 2007 से 2016 के बीच भारत में पचहत्तर हजार विद्यार्थियों की खुदकुशी का आंकड़े से भी हम कोई सबक नहीं लेते तो फिर हमें एक बड़े संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शैक्षणिक असफलता का भय इतना व्यापक हो गया है कि उसके सामने जीवन तुच्छ नजर आने लगा है। सवाल है कि क्या हत्या और आत्महत्या समस्याओं का एकमात्र समाधान रह गए हैं? अगर इसका जवाब 'हां' है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य, परिवार, या फिर बाजार? आज समाज पर उपभोक्तावाद इतना हावी है कि समृद्धि की चाहत में भावनाएं, रिश्ते, प्रेम सब कुछ हाशिये पर कर दिया गया है। बच्चों को हार और जीत दोनों का सामना करना सिखाना चाहिए। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, इस सोच को उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया जाए। जिस विषय के प्रति उसमें स्वाभाविक रुचि है उस क्षेत्र में ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, न कि उस पर अपनी इच्छा थोपी जाए। किसी परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है, यह तर्क उसकी चेतना का हिस्सा होना चाहिए।

शख्सियत का खजाना

विलास जोशी

दुनिया मेरे आगे

एक व्यक्ति के लिए उसकी शख्सियत पुष्प में सुगंध की तरह होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी शख्सियत से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हमारे शरीर की भाषा भी हमारी शख्सियत को बयान करती है और वह हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। कई बार यह भी अनुभव किया जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हम उसकी शख्सियत से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। मसलन, उसके हावभाव, उसके बालों की स्टाइल और उसके शरीर की भाषा, जिसे 'बॉडी लैंग्वेज' भी कहते हैं।

शरीर की भाषा एक ऐसी बात है, जिसकी तरफ आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह किसी की शख्सियत को प्रभावी बनाती है या उसके प्रभाव को नष्ट भी करती है। कहते हैं कि शख्स ही नहीं बोलता, बल्कि उसका शरीर भी बोलता है। जैसे किसी की आंखें बोलती हैं।

हमारी शख्सियत दो बातों पर निर्भर करती है। एक, हम क्या कहना चाहते हैं और दूसरा, हमारे शरीर की भाषा उसे किस प्रकार सबके सामने प्रस्तुत करती है। हमारे बात कहने या प्रस्तुत करने की कला ही हमारी शख्सियत में चार चांद लगाती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी शख्सियत में इजाफा हो तो उसके लिए उसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसका आत्मविश्वास किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि कोई उसके साथ किस ढंग से पेश आता है। इसी से संबंधित एक मर्मस्पर्शी वाकया कुछ दिन पहले पढ़ा। एक व्यक्ति चर्च में गया। रविवार का दिन था। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच उसके मोबाइल की घंटी बज गई। प्रार्थना के बीच घंटी की आवाज किसी को भी पसंद नहीं आई। फिर चर्च के पादरी ने उसे कुछ लोगों के सामने चार बातें सुनाईं। इसके अलावा, प्रार्थना के बाद लोगों ने उसे अलग-अलग सलाह देना शुरू किया। ये सब बातें सुनने के बाद उसका मिजाज खराब हो गया। परेशानी के आलम में ही शाम को एक होटल में गया। बैरे के हाथ से गलती से उसकी कमीज पर चाय का कप गिर गया। बैरे ने उससे माफी मांगी और उसे फिर दूसरे कप में चाय लाकर दी। इस बीच होटल का मैनेजर उसके पास आया और उसे गले लागते हुए बोला- 'सॉरी, आप परेशान न हो, गलतियां किससे नहीं होती हैं भला?' उस दिन के बाद वह व्यक्ति कॉफी पीने सिर्फ उसी होटल में जाने लगा।

ये दो घटनाएं हमारे सामने हैं। पहली में उस शख्स को चर्च में अपनी गलती के लिए सबकी बातें सुननी पड़ीं। दूसरी तरफ होटल में उसके साथ दोस्ताना व्यवहार हुआ। उसने गलती के लिए वेटर को माफ कर दिया। मनोविज्ञान कहता है कि कितनी भी विकट परिस्थिति में कोई व्यक्ति दूसरे के साथ किस प्रकार से पेश आता है, इस बात पर उसकी शख्सियत तय होती है और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है।

किसी भी व्यक्ति की शख्सियत इस बात पर निर्भर करती है कि जब वह लोगों के बीच जाता है, तब वह उनको किस प्रकार निहारता है, अपने परिचित को कैसे खोजता है या अपरिचित लोगों के साथ कैसे मेलजोल करके उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता है। जिसके स्वभाव में नए लोगों से मिलने का आकर्षण हो, वह बहुत जल्दी किसी को भी अपना बनाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे समय में वह अपनी शख्सियत के खुलेपन के गुण का उपयोग कर वहां उपस्थित लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी में रुचि लेंगे तभी सामने वाला भी आपमें रुचि लेगा। जब कोई व्यक्ति किसी से बातें करते समय रोचक अंदाज से अपनी बात कहता है और बात करने के दौरान मजेदार किस्से या अपने जीवन का कोई दिलचस्प अनुभव सुनाता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।

अक्सर यह अनुभव किया जाता है कि कुछ वक्ता जब अपना संबोधन देते हैं, तो उनके व्याख्यान के दौरान उनकी आंखें श्रोताओं या दर्शकों से सीधी बात करती रहती हैं। वे अपनी आंखों के रास्ते से श्रोताओं के दिल के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। उद्बोधन देते समय उनके शरीर के सारे महत्त्वपूर्ण अवयव मानो श्रोताओं से बातचीत करते महसूस होते हैं। किसी भी शख्स को अपनी शख्सियत बनाए रखने के लिए मुस्कान बहुत सहयोग करती है। आज भी हजारों दर्शक देवानंद और राजेश खन्ना की मुस्कान के मुरीद हैं और इसी वजह से इन दोनों सितारों की शख्सियत लोगों के दिलोदिमाग से आज भी जुदा नहीं हो पाई है।

मनोविदों का कहना है कि हर शख्स के शरीर का हर हिस्सा उसकी शख्सियत का आईना होता है। वह लोगों से बात करते समय किस तरफ देखता है, अपने हाथ कहां रखता है और अगर वह खड़ा होकर बात कर रहा है तो उसने अपने पैर किस तरह रखे हैं... आदि। कहते हैं कि जब हम बातें करते हैं, तब केवल हमारा मुंह नहीं बोलता, बल्कि हमारे शरीर के ज्यादातर अंग भी बोलते हैं। जिस शख्स को शरीर की भाषा पढ़नी आ गई, समझिए, उसे शख्सियत का खजाना मिल गया।

नफरत के विरुद्ध

संपादकीय 'नफरत का दायरा (3 मई) सामयिक भी है और जरूरी भी। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में अनुमान था कि इक्कीसवीं सदी में धर्म के नाम पर होने या फैलाई जाने वाली नफरत का दायरा सिकुड़ कर स्वतः समाप्त हो जाएगा और धरती पर रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग विज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आपस में सद्भाव से रहने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ मनुष्य ने अपने जीवन को आरामदायक और पीड़ा रहित बनाने के लिए तो किया लेकिन विभिन्न समुदायों और संप्रदायों के बीच अतीत की कुछ भूलों की वजह से नफरत की जो छोटी-छोटी दीवारें मौजूद थीं, वे बीतते वक्त के साथ और ऊंची होती चली गईं। इंसान का एक-दूसरे पर से भरोसा उठता चला गया और पूरी दुनिया हर इंसान पर संदेह करने लगी। इसी संदेह की बदौलत आज आप कहीं भी जाएं, सुरक्षाकर्मियों के हाथ आपके शरीर को टटोलने लगते हैं। चंद आतंकवादियों ने दुनिया को मजबूर कर दिया कि वे अपने यहां आने वाले अतिथियों पर भी भरोसा न करें। विभिन्न देशों में जिस धन का उपयोग गरीबी को मिटाने के लिए किया जा सकता था, उसका उपयोग आज सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।

बहरहाल, नफरत का यह दायरा जिन कारणों से बढ़ा और बढ़ता जा रहा है, उसमें सबसे प्रमुख कारण विभिन्न मानव समूहों की 'मैं श्रेष्ठ हूं' वाली सोच से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दबावों के चलते जहां एक तरफ दुनिया में रंगभेद के आधार पर दूसरे को अपने से हीन समझने की भावना में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज होने के लिए दुनिया में कुछ राजनीतिक धर्म का बेजा इस्तेमाल करने लगे हैं। धर्म ग्रंथों का उपयोग सहिष्णुता और सद्भाव बढ़ाने के बजाय अलगाववाद और वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ वे उदाहरण खोजे जा रहे हैं जिनसे नफरत के दायरे को और अधिक विस्तार दिया जा सके और अब तो इसमें झूठी कहानियां भी रोपी जा रही हैं। जिस सोशल मीडिया का उपयोग समाज में शांति बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए था, वही आज नफरत के सौदागरों के लिए एक अचूक हथियार बन गया है।

बहरहाल, उम्मीद है कि दुनिया को और अधिक बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखने वाले लोग अपनी कोशिशों से बढ़ती हुई नफरत पर अंकुश लगाने में सफल होंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो देर-सबेर यह नफरत पूरी दुनिया को सीरिया में तब्दील कर देगी।

● *सुभाष चंद्र लखेड़ा, द्वारका, नई दिल्ली*

शंका और समाधान

लोकतांत्रिक प्रणाली में मताधिकार काफी महत्त्वपूर्ण है। जनतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक (जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है) को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए वोट देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लंबे समय तक मतदान मतपत्र से ही कराया जाता रहा पर अब इसके लिए ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ईवीएम में गड़बड़ियों की खबरें भी सुनने को मिलती रही हैं। जहां कई राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इसे हटाने और फिर मतपत्र से ही मतदान कराने की मांग की है वहीं चुनाव आयोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर अड़ा है। ऐसे में मतदाताओं के शंकाओं को दूर करना चुनाव आयोग की अहम जिम्मेदारी है।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरु, मधेपुरा, बिहार*

संकट का सबक

भारत में विमानन उद्योग ने उद्यमियों को वैसे ही आकर्षित किया है जैसे कीट-पतंग आग की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ही कंपनियां सफल हो पाई हैं। एक समय देश की सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी रही जेट एयरवेज की हालत बताती है कि देश का विमानन उद्योग किस संकट से गुजर रहा है। जबकि हाल के वर्षों में भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने दो अंकों में वृद्धि दर्ज की है और भारत को इस मामले में संभावनाओं वाले देश के रूप में देखा जाता रहा है। दरअसल, सस्ती विमान सेवाएं शुरू होने के बाद पिछले एक-डेढ़ दशक के दौरान विमान यात्रियों का एक नया वर्ग भी तैयार हुआ। इसके बावजूद विमानन कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो रही थीं, तो कहीं न कहीं यह नीयत और नियंत्रण दोनों का मामला है।

देश में जिस तरह से सरकार और आमजन ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई, वह विमानन उद्योग के लिए आशाजनक स्थिति थी। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार देश का विमानन उद्योग दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहा है। यदि ऐसे समय में विमानन कंपनियां बंद हो रही हैं, तो उस कंपनी के नीतियां और नियंता ही जिम्मेदार हैं। हैरानी की बात यह है कि 2012 में ऐसी ही हालत में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी, इसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। इस समस्या से निपटने में सरकार को अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा को बढ़ाना होगा। साथ ही इस क्षेत्र में ऐसे उपाय करने की जरूरत है, जिनसे निवेशकों का विश्वास बना रहे।

● *दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

बढ़ते साइबर अपराध

सरकार डिजिटल लेन-देने को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसी बीच साइबर चोर भी काफी सक्रिय हो गए हैं। साइबर चोर लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर, फोन कॉल करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी पूछ कर धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी झांसें में आकर अपनी खून-पसीने की कमाई बर्बाद न करें। साइबर चोरों की धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। इसका सभी को खयाल रखना चाहिए कि अपने क्रेडिट, डेबिड कार्ड, इनके सीवीवी और ओटीपी किसी के साथ भी साझा न करें।

देश में बढ़ते साइबर अपराधों या धोखाधड़ी मामलों से निपटने के लिए साइबर क्राइम सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए। अगर किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम किसी भी ब्रांच में कोई शिकायत करता है तो उस पर एकदम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि साइबर चोरों को संभलने का मौका न मिले। रिजर्व बैंक को भी चाहिए कि इसके लिए वह बैंकों को विशेष हिदायतें दे कि वे अपनी कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाएं, खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली